फा.सं.जेड-14014/2/2020-जीसी (ई-3010062)

भारतसरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,

नईदिल्ली-110011

दिनांक: 17.02.2020

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: जनवरी, 2020 के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिकसारके संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त दिनांक 17.08.2018 एवं 11.10.2018 के पत्रांक 1/26/1/2018-कैब. का उल्लेख करने और जनवरी, 2020 माह के लिए भूमि संसाधन विभाग के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अनुलग्नक: यथोक्त।

(अर्जुन राणा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23044653

सेवामें,

मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपिप्रेषित:-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सभी सचिव, भारत सरकार।
6. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
7. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव
2. माननीया ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के निजी सचिव

जनवरी, 2020 माह के दौरान भूमि संसाधन विभागद्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और मुख्य कार्यकलापों का मासिक सार

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, जनवरी, 2020 माह के दौरान 40 परियोजनाओं (02 राज्यों में) के पूरा होने की सूचना प्राप्त हुई है और इस प्रकार वर्ष 2019-20 के दौरान पूरी हुई परियोजनाओं का योग 712 (13 राज्यों में) हो गया है और 31 जनवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार, पूरी हुई परियोजनाओं का कुल योग 3076 हो गया है। यह वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान 28 राज्यों में संस्वीकृत कुल 6382 [8214 (संस्वीकृत)- 1832 (राज्यों का हस्तांतरित)] वाटरशेड विकास परियोजनाओं में से हैं। नीरांचल सहित डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अंतर्गत वाटरशेड विकास के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान (जनवरी, 2020 तक) राज्यों को 1051.12 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। जनवरी, 2020 माह के दौरान राज्यों को 79.53 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

व्यापार करना आसान बनाना- दिल्ली और मुम्बई में सम्पत्तियों के रजिस्ट्रीकरण तथा कोलकाता और बेंगलूरू में विभिन्न सुधारक उपायों को अग्रता के आधार पर लागू करने के लिए प्रगति की समीक्षा करने हेतु दिनांक 14.01.2020 को एक बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों और उसके हितधारकों ने भाग लिया।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने, अप्रयुक्त शेष राशियों, आउटपुट-आउटकम संसूचकों और पीएफएमएस इत्यादि के बारे में 12 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ 16.01.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।

सचिव, भूमि संसाधन विभाग की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) को निरंतर रूप से कार्यान्वित करने के बारे में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों के अध्यक्षों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) के एनएएसी परिसर, पूसा रोड, नई दिल्ली में सम्मेलन का आयोजन किया गया। नीति आयोग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। वाटरशेड परियोजनाओं की नई जेनरेशन के लिए एक समान दिशा-निर्देशों के मसौदे (एनआरएए द्वारा तैयार) पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया।

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए जयपुर में 24 जनवरी, 2020 को क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त सम्मेलन में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन और द्वीव और दादरा और नगर हवेली से वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

आरईडब्ल्यूएआरडी परियोजना के बारे में विचार-विमर्श करने हेतु विश्व बैंक के प्रतिनिधियों और ओडिशा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भुवनेश्वर, ओडिशा में 20 जनवरी, 2020 को एक बैठक का आयोजन किया गया।